जा रहे अन्य शिक्षा संस्थानों में 26 जनवरी, 15 अगस्त 30 जनवरी, 14 नवम्बर, जैसे राष्ट्रीय दिवस मनाये जाते हैं और क्या उन्हें मनाने के बारे में सभी सम्बन्धित प्राधिकारियों को सरकारी अनुदेश जारी कर दिए गये हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार यह सुनिश्चित करती है कि इन दिवसों को वस्तुतः मनाया जाता है; यदि हां, तो इसकी पुष्टि के लिए किस प्रक्रिया का अनुसरण किया जाता है?

शिक्षा और समाज कल्याण मंत्री (श्री एस० बी० चव्हाण) : (क) और (ख). 26 जनवरी और 15 अगस्त जैसे राष्ट्रीय दिवस गृह मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों तथा संघ शासित क्षेत्रों की सरकारों/प्रशासनों को जारी की गई स्थायी हिदायतों के अनुसार सारे देश में बहुत अच्छी तरह मनाए जाते हैं। भारत के स्वतंत्रता संग्राम में जिन लोगों ने अपना जीवन न्यौछावर किया था उनकी याद में 30 जनवरी के दिन को दो मिनट का मौन धारण करने के लिए भी गृह मंत्रालय ने हिदायतें जारी की हैं। इन हिदायतों को कार्यान्वित करना सम्बन्धित राज्य सरकारों/संघ शासित क्षेत्रों की जिम्मेदारी है। जहां तक केन्द्रीय विद्यालयों का सम्बन्ध है, कार्यान्वयन की जांच वास्तविक निरीक्षणों और विद्यालयों द्वारा रखे गए रिकार्डों के माध्यम से की जाती है।

Shortage of Wheat products in Tamil Nadu

3838. SHRI C. CHINNASWAMY: Will the Minister of AGRICULTURE be pleased to state:

(a) whether Government are aware that there is acute shortage of wheat products in Tamil Nadu; and

(b) if so, the steps taken by Government to remove this shortage?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF AGRICULTURE AND RURAL RECONSTRUCTION (SHRI R. V. SWAMINATHAN): (a) and (b). Yes, Sir. Some shortage of wheat products has been reported. The Tamil Nadu Government have asked the Tamil Nadu Civil Supplies Corporation and Co-operatives which feed the public distribution system to distribute more wheat products. Besides, as there are no restrictions on movement of wheat products, traders are free to move any quantity from other States for consumption in Tamil Nadu.

महिलाओं के लिए होस्टल

3839. **श्री राम अवध** : क्या **निर्माण और आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का देश के बड़े शहरों में कामकाजी महिलाओं के लिए होस्टल बनाने का विचार है, और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में तथ्य क्या हैं;

संसदीय कार्य तथा निर्माण और आवास मंत्री (श्री भीष्म नारायण सिंह) : (क) तथा (ख). आवास राज्य विषय होने से नौकरी करने वाली महिलाओं के लिए होस्टलों का निर्माण राज्य सरकारों के क्षेत्राधिकार में आता है। आवास तथा नगर विकास के लिए राज्य मंत्रियों से कलकत्ता में दिसम्बर, 1976 में हुए अपने सम्मेलन में यह सिफारिश की थी कि होस्टल निर्माण का एक चरणबद्ध कार्यक्रम बनाने के लिए राज्य

सरकारों को विभिन्न शहरों और कस्बों में नौकरी करने वाली महिलाओं की होस्टल की आवश्यकता का मूल्यांकन करना चाहिए। सम्मेलन की सिफारिश को सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य प्रशासनों को आवश्यक कार्यवाही करने के लिए प्रचालित किया गया था।

Accommodation to the Children's of Retiring Govt. Employees

3840. SHRI V. SREENIVASA PRASAD:
SHRI T. S. NEGI:
SHRI OSCAR FERNANDES:
SHRI BALASAHEB VIKHE PATIL:
SHRI CHANDRABHAN ATHARE PATIL:
DR. VASANT KUMAR PANDIT:
SHRI DAYA RAM SHAKYA:
SHRI RAM VILAS PASWAN:

Will the Minister of WORKS AND HOUSING be pleased to refer to the reply given to Unstarred Question No. 1738 on the 23rd June, 1980 regarding Government accommodation to the children of the retiring Government employees and state:

(a) whether a final decision in this regard has since been taken;

(b) if so, what; and

(c) if not, what are the hurdles coming in the way of the Government in arriving at an early final decision in this regard?

THE MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS AND WORKS AND HOUSING (SHRI BHISHMA NARAIN SINGH): (a) No, Sir.

(b) Does not arise.

(c) The matter is under consideration and a final decision is expected to be taken shortly.

लखीमपुर खेरी जिले में सम्पूर्ण नगर में सहकारी चीनी मिल की स्थापना करना

3841. **श्रीमती उषा वर्मा** : क्या कृषि मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लखीमपुर खेड़ी जिले में सम्पूर्णानगर में एक सहकारी चीनी मिल की स्थापना करने के लिये कोई प्रस्ताव उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कई महीने पूर्व भेजा गया था, राज्य सरकार ने इसकी सिफारिश की थी लेकिन इस चीनी मिल की स्थापना के लिये अब तक अनुमति नहीं दी गई है ;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं और यदि नहीं, तो इस चीनी मिल की स्थापना के लिये एक लाइसेंस कब तक दिया जायेगा ; और

(ग) क्या सरकार का विचार उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सिफारिश की गई 1250 टन प्रतिदिन की पेराई क्षमता वाली सम्पूर्णानगर क्षेत्र में सहकारी क्षेत्र में एक चीनी मिल की स्थापना के लिये लाइसेंस देने का है ?

कृषि तथा ग्रामीण पुनर्निर्माण मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर० वी० स्वामीनाथन): (क) से (ग). जी, हां। लखीमपुर खेड़ी जिले में स्थित सम्पूर्णानगर में 1250 मीटरी टन प्रतिदिन की क्षमता की सहकारी चीनी मिल स्थापित करने के लिए लाइसेंस प्रदान करने हेतु एक आवेदन पत्र प्राप्त हुआ है, जिसे उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा अभिस्तावित किया गया है। प्रस्तावित कारखाने को स्थापित करने की व्यवहार्यता के बारे में सरकार